चैलेंज फॉर चेंज में दे रहे अपने प्रोजेक्ट

प्रदेश की चुनौतियां हल करने में स्टार्टअप निभा रहे भूमिका

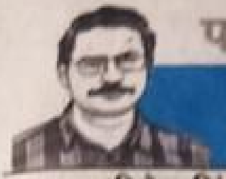

पत्रिका खास खबर

अभिषेक सिंघल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . प्रदेश में स्टार्टअप प्रदेश में सुरक्षित पानी, खेती में पानी की बचत, बीमारियों की शीघ्र पहचान, बंजर भूमि को उपयोगी बनाने और गांवों को स्मार्ट बनाने जैसे उपायों से राजस्थान की समस्याओं को हल करने में आगे आ रहे हैं। चैलेंज फॉर चेंज के जरिए स्टार्टअप इसके लिए अपने आइडिया दे रहे हैं। प्रदेश में स्टार्टअप के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से पांच साल में 284 स्टार्टअप को साढ़े पन्द्रह करोड़ से ज्यादा की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

मार्च में 46 स्टार्टअप को मिला सहारा

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से हाल ही में कुल 46 स्टार्टअप को दो करोड़ 67 लाख स्वीकृत किए हैं। इनमें ऑर्गेनिक खेती, आईटी कंसल्टिंग, साइबर सिक्यूरिटी, ई लर्निंग, स्किल डवलपमेंट, मेडिकल डिवाइस, डेयरी फार्मिंग, हेल्थ वेलनेस, आर्ट हैंडीक्राफ्ट, रिन्युएबल एनर्जी व रोजगार क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप हैं।

12 से शुरुआत अब 171 को सहायता: वर्ष 2017-18 में 12 स्टार्टअप को 9 लाख 20 हजार का अनुदान दिया गया था। 18-19 में 74 स्टार्टअप को पांच करोड़ उनसठ लाख अनुदान दिया गया। कोरोना संकट के कारण 2019-20 में 27 स्टार्टअप को केवल सस्टेनेंस अलाउंस के रूप में 32 लाख दिए गए तो साल 2021-22 में 171 स्टार्टअप को नौ करोड़ पचास लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

सुझा रहे उपाय

प्रदेश की विषम परिस्थितियों के कारण उत्पन्न स्थितियों से पार पाने के उपाय सुझाने के लिए स्टार्टअप को सरकार की ओर से दो करोड़ रुपए तक का कार्य इन स्टार्टअप को बिना निविदा के दिए जाने की योजना है। प्रमुख सुझावों में नहर में रिसाव को चिन्हित करना, सुरक्षित पानी मुहैया करवाना, अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों की बुवाई में कमी लाना, बंजर भूमि का उपयोगी भूमि में परिवर्तन जैसे उपाय शामिल हैं। इस साल की चुनौतियों में एआई से बीमारियों की पहचान, सड़कों पर ब्लैक स्पॉट मैनेजमेंट सिस्टम सहित अन्य आइडिया शामिल हैं। इसके लिए 11 अप्रेल तक स्टार्टअप और 30 अप्रेल तक स्टूडेंट एंट्री कर सकते हैं।

स्टार्टअप को शुरुआती प्रोजेक्ट की जरूरत होती है। सरकार के सामने आने वाली समस्याओं को शार्क टैंक की तर्ज पर प्रतियोगिता के जरिए चुने हुए सोल्यूशन्स को प्रोक्योरमेंट की लम्बी प्रक्रिया से बचाते हुए दो करोड़ तक सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

- संदेश नायक, कमिश्नर, डीओआईटी, राजस्थान

जयपुर में डीजल दूसरी